दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक

7 | 3 मुझे लिंग परिवर्तन करना है... | 5 सपा ने मांगी 65 और कांग्रेस ने 40 लोकसभा सीटें | 8 भारत ने रचा इतिहास

UPHIN51019 | वर्षः 01, अंकः 9 | पृष्ठ संख्याः 8 | मूल्यः 1.00 रू. | सोमवार 25 सितम्बर, 2023

बिहार में एक और पुल धंसा

तेज बहाव में सात खंभे ने जगह छोड़ी, आवागमन बंद कराया गया

पटना। जमुई में बरनार नदी पर बना सोने-चुरहेत काजवे पुल अचानक धंस गया। पानी की तेज बहाव के कारण पुल का तीन से दस नंबर पिलर (खंभा) क्षतिग्रस्त होकर धंस गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुल धंसने की खबर से सुन इलाके के लोग यहां पहुंचे। इसके बाद प्रशासन को जानकारी दी।

प्रशासन फौरन पहुंची और आवागमन पर रोक लगा दिया। फिलहाल पुल के दोनों छोर पर बैरिकैडिंग कर दी गई है। आवागमन ठप होने के कारण कई गांव के लोगों का शहर से संपर्क टूट गया है।

प्रशासन ने परिचालन पर पूरी तरह से लगा दिया रोक

जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सोनो चुरहेत काजवे मार्ग पर परिचालन को पूरी तरह रोक दिया गया। पुल के दोनों ओर बेरिकेडिग कर दी गई है।

प्रशासन के अनुसार, लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर उफान पर है। पानी की तेज बहाव के कारण पुल धंस गया। यह पुल सोनो प्रखंड मुख्यालय को पश्चिम क्षेत्र से जोड़ती है। इससे आसपास के कई गांव का संपर्क टूट गया। वही पुल धंसने ने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची और एहतियात बरतते हुए सोनो चुरहेत काजवे मार्ग पर परिचालन को पूरी तरह रोक दिया गया।

पुल के दोनों ओर बेरिकेडिंग कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि पुल की मरम्मती का काम जल्द से जल्द करवाया जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीण परेशान, मुख्यालय जाने के लिए इसी पुल का उपयोग करते थे

स्थानीय लोगों का कहना है कि गुरुवार से मूसलाधार बारिश हो रही है। पानी के तेज बहाव के कारण बरनार नदी पर बना सोनो चुरहेत काजवे पुल का तीन से १० पिलर नदी में धंस गया है। सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी राजेश कुमार, थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार व एसआई विपिन कुमार पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। इन्होंने क्षतिग्रस्त काजवे पुल का मुआयना किया। इसके बाद पुल पर परिचालन पूरी तरह बंद कर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पुल से कई गांवों के लोगों का आना-जाना लगा रहता है। काजवे, चुरहेत समेत अन्य गांवों के लोग प्रखंड मुख्यालय आने-जाने के लिए इसी पुल का उपयोग करते है। कई छोटे और बड़े वाहनों का भी परिचालन लगा रहता है। लेकिन पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यहां के ग्रामीणों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

खतरे ग्लोबल हैं तो उससे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिएः मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन २०२३ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसमूह को भी संबोधित किया। जानकारी के लिए बता दें कि बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा २३ और २४ सितंबर को न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन २०२३ का आयोजन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन २०२३ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसमूह को भी संबोधित किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, २३ और २४ सितंबर को न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन २०२३ का आयोजन किया जा रहा है। इसे बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय वकीलों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है। किसी भी देश के निर्माण में वहां की कानूनी बिरादरी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से न्यायतंत्र भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं।

आजादी की लड़ाई में कानूनी बिरादरी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई

दिल्ली के विज्ञान भवन से पीएम मोदी कहा, हाल ही में भारत की आजादी के ७५ साल पूरे हुए। आजादी की लड़ाई में कानूनी बिरादरी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। दुनिया आज भारत पर विश्वास क्यों करती है, इसमें भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है।

महिला आरक्षण का किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि आज यह सम्मेलन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को ३३ः आरक्षण देने का कानून पास किया है। उन्होंने आगे कहा कि कानूनी पेशेवरों के अनुभव ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया है। आज भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है, उसमें भी भारत की न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है।

ऐसा करने वाला भारत बना दुनिया का पहला देश

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ ही दिन पहले जी२० के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी प्रजातंत्र, जनसांख्यिकी और हमारी कूटनीति की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज ही के दिन भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना था।पीएम मोदी ने आगे कहा कि साइबर आतंकवाद हो, मनी ल न्ड्रिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, विभिन्न मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। इसके लिए अलग-अलग देशों के कानूनी ढांचा को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा।

इस सम्मेलन का उद्देश्य ?

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक बातचीत और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना।

विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत करना।

पहली बार हो रहा देश में आयोजित

जानकारी के लिए बता दें कि यह सम्मेलन देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमेबाजी में चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी, पर्यावरण कानून जैसे कई विषयों पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित न्यायाधीशों, कानूनी पेशेवरों और वैश्विक कानूनी बिरादरी के नेता भी शामिल होंगे।

नए संसद भवन पर हुई रार

वास्तुकला अगर लोकतंत्र को मार सकती है तो पीएम मोदी सफल हो गए हैं

नई दिल्ली। जयराम रमेश ने लिखा कि यह असल में पीएम मोदी के उद्देश्यों को पूरा करती है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहना चाहिए। चार दिनों के बाद मैंने महसूस किया है कि संसद की नई इमारत के अंदर और लाबी में बातचीत खत्म हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर संसद की नई इमारत की आलोचना की है। जयराम रमेश ने लिखा कि पूरे जोर-शोर से संसद की नई इमारत ल न्च की गई थी। यह असल में पीएम मोदी के उद्देश्यों को पूरा करती है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहना चाहिए। चार दिनों के बाद मैंने महसूस किया है कि संसद की नई इमारत के अंदर और ल बी में बातचीत खत्म हो गई है। अगर वास्तुकला लोकतंत्र को मार सकती है तो संविधान को दोबारा लिखे बिना ही प्रधानमंत्री सफल हो चुके हैं।

पुरानी इमारत में एक आभा थी

जयराम रमेश ने लिखा कि एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत होगी क्योंकि ह ल बिल्कुल भी आरामदायक नहीं हैं। पुरानी इमारत में एक आभा थी, साथ ही यहां बातचीत करना भी आसान था। एक सदन से दूसरे सदन जाने में, सेंट्रल ह ल में और क रिडोर्स में चलना-फिरना आसान था। नई संसद में सदन को चलाने के लिए दोनों सदनों के बीच का ब न्ड कमजोर हुआ है। पुरानी इमारत में अगर आप रास्ता भूल जाते थे, तो रास्ता मिल जाता था क्योंकि यह गोलाकार था लेकिन नई इमारत में यदि आप रास्ता भूल जाते हैं तो आप भूलभुलैया में खो जाते हैं। पुरानी इमारत में खुलेपन का एहसास होता था, जबकि नई इमारत में बंद जगहों पर घुटन महसूस होती है।

जयराम रमेश ने लिखा कि संसद भवन में घूमने का आनंद गायब हो गया है। मैं पुरानी इमारत में जाने के लिए उत्सुक रहता था लेकिन नई इमारत पीड़ादायक है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइन से हटकर कई सहकर्मी भी ऐसा महसूस करते हैं। मैंने सुना है कि सचिवालय के कर्मचारी भी नए डिजाइन से खुश नहीं हैं। ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले से कोई परामर्श नहीं किया जाता है। जयराम रमेश ने लिखा कि शायद २०२४ में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

सम्पादकीय

भारत के लिए आसान नहीं है मुद्रास्फीति से लड़ना

अगस्त महीने के लिए भारत की आधिकारिक मुद्रास्फीति दर 6.83 प्रतिशत है जो पिछले महीने की दर से 7.44 प्रतिशत से नीचे है।

भारत की राजकोषीय स्थिति स्वीकार की गई स्थिति से कहीं अधिक गंभीर है। यदि हम ऋण सेवा अनुपात की तुलना करते हैं यानी सरकार के राजस्व का कितना हिस्सा कर्ज के बढ़ते पहाड़ जैसे ब्याज का भुगतान करने के लिए जाता है तो हम पाते हैं कि भारत का औसत सभी देशों के औसत से ऊपर है। उच्च घाटे के कारण ब्याज दर भी उच्च बनी रहती है जिससे आवास, अचल संपत्ति और वास्तव में सभी औद्योगिक परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नुकसान होता है। अगस्त महीने के लिए भारत की आधिकारिक मुद्रास्फीति दर ६.८३ प्रतिशत है जो पिछले महीने की दर से ७.४४ प्रतिशत से नीचे है। यह अभी भी ६ प्रतिशत की अधिकतम दर से ऊपर है जो भारतीय रिजर्व बैंक की रेडलाईन है। जब से मौद्रिक नीति २०१६ में मुद्रास्फीति लक्ष्य पर स्थानांतरित हुई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए मुद्रास्फीति का स्वीकार्य बैंड २ से ६ प्रतिशत के बीच है। पिछले बारह महीनों में यह सातवीं बार है जब मासिक मुद्रास्फीति दर ६ फीसदी से ऊपर है। क्या यह आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के लिए चिंताजनक नहीं होगा? उन्हें मुद्रास्फीति को कम करने के लिए धन की आपूर्ति और सख्त करने की आवश्यकता है लेकिन इस उम्मीद में कि मुद्रास्फीति अपने आप कम हो जाएगी उन्होंने ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने का विकल्प चुना है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी संकेत दिया है कि मुद्रास्फीति कुछ समय तक ऊंची बनी रहेगी।

भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपभोग टोकरी में लगभग ४५० विभिन्न वस्तुओं का भारित औसत शामिल है जो ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग है परन्तु इसका लगभग ४६ प्रतिशत भोजन और संबंधित वस्तुओं में चला जाता है। इसलिए यदि खाद्य मुद्रास्फीति अधिक है तो स्वाभाविक रूप से समग्र मुद्रास्फीति अधिक होती है।

खाद्य मुद्रास्फीति जो लगभग ४६ प्रतिशत है, वर्तमान में १० प्रतिशत पर चल रही है। इसका कारण सब्जियों, तिलहनों, दालों, दूध और यहां तक कि अनाज की बढ़ती कीमतें हैं। भारत ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाने या विभिन्न ंषि उत्पादों पर भारी निर्यात कर लगाने के संयोजन का उपयोग किया है। इनमें गेहूं, चावल, चीनी और प्याज शामिल हैं। यह उन किसानों की कमाई को प्रभावित करता है जो निर्यात से आकर्षक मुनाफे पर नजर रख रहे थे। उदाहरण के लिए भारत ने २०२२ में ७०.४० लाख टन उबला हुआ चावल निर्यात किया था लेकिन अब इस पर २० फीसदी का जबरदस्त निर्यात शुल्क है।

दुनिया के चावल निर्यात में भारत का हिस्सा ४० प्रतिशत है और भारत के प्रतिबंधों ने दुनिया में चावल की अतिरिक्त कमी पैदा कर दी है। भारत से निर्यात प्रतिबंधों ने चीन, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे आयातक देशों को प्रभावित किया है। फिलीपींस में चावल की भारी कीमतों के कारण एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। क्या प्रतिबंध या निर्यात कर ने भारत में चावल की मुद्रास्फीति को कम कर दिया है? वास्तव में नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से टूटे हुए चावल (जिस पर निर्यात कर लागू होता है) का उपयोग इथेन ल उत्पादन के लिए हो रहा है। कारों के लिए ईंधन बनाने के लिए खाद्यान्न का उपयोग करना एक विवादास्पद नीति है, खासकर उस समय जब दुनिया उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का सामना कर रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन (एफएओ) का चावल मूल्य सूचकांक अगस्त में ६.८ प्रतिशत बढ़ा है और अब यह १५ साल के उच्च स्तर पर है। इस तरह भारत में महंगाई फैलनी तय है। इथेन ल नीति कीमती ड लर को बचाने की कोशिश से प्रेरित है जिसे हम कच्चे तेल के आयात पर खर्च करते हैं। तो भी अगर घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति ड लर भुगतान करने की कीमत है तो हमें ईंधन उत्पादन के लिए खाद्य फसलों का उपयोग करने के बारे में सावधानीपूर्वक सोचना होगा।

खाद्य मुद्रास्फीति से परे कच्चे तेल के बारे में हमारा नजरिया भी उच्च कीमतों की आशंका बढ़ाता है। रूस और सऊदी अरब द्वारा आपूर्ति में कटौती के कारण तेल की कीमतें पहले ही ८५ डालर को पार कर गई हैं और ऊंची ही बनी रहेंगी। चूंकि यह भारत के आयात पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है इसलिए संभावना है कि भारतीय रुपया ८३ से ८५ तक गिर जाएगा। तेल आयात बिल को केवल स फ्टवेयर और आईटी सेवाओं के उम्मीद से अधिक निर्यात से हराया जा सकता है। ऐसा कहना आसान है लेकिन इसे अमल में लाना कठिन है क्योंकि स फ्टवेयर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से मंदी नजर आ रही है। बेशक, भारत की स फ्टवेयर सेवाओं के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ष्टिकोण बहुत मजबूत बना हुआ है। उद्योग निकाय नैसक म द्वारा ऐसा ही संकेत दिया गया है।

खाद्य मुद्रास्फीति तेल की कीमतों और डालर की विनिमय दर में गिरावट के अलावा राजकोषीय घाटे का आकार मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का प्रमुख योगदान है। भारत उच्च घाटे में चल रहा है और राष्ट्रीय ऋण भी बढ़ रहा है। घाटे को नियंत्रित करने के सभी प्रयास व्यर्थ प्रतीत होते हैं। बेशक, महामारी के दौरान घाटे को बढ़ाना पड़ा क्योंकि सरकार को मुफ्त भोजन, सब्सिडी वाले ऋण और पर्याप्त तरलता के रूप में आपातकालीन बचाव उपायों का उपयोग करना पड़ा लेकिन कुछ फैसलों से भौंहें तन सकती हैं। उदाहरण के लिए, ४८ महीने से अधिक समय से चल रही मुफ्त खाद्यान्न योजना से सरकारी खजाने पर कुल ४.५ लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है। कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए मंत्रिमंडल ने हाल ही में १०.७ खरब रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की। एक संसदीय प्रश्न के उत्तर के अनुसार पिछले ६ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग १४.५६ लाख करोड़ रुपये के खराब ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है। इसके राजकोषीय निहितार्थ हैं क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा इक्विटी पूंजी बैंकों में डाली जानी है। बट्टे खाते में डालना एक कारक हो सकता है जिससे फंसे कर्ज का अनुपात कम होगा और बैंकिंग क्षेत्र की सेहत सुधरेगी लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजकोषीय खर्च बहुत बढ़ा हुआ है और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा है।

भारत की राजकोषीय स्थिति स्वीकार की गई स्थिति से कहीं अधिक गंभीर है। यदि हम ऋण सेवा अनुपात की तुलना करते हैं यानी सरकार के राजस्व का कितना हिस्सा कर्ज के बढ़ते पहाड़ जैसे ब्याज का भुगतान करने के लिए जाता है तो हम पाते हैं कि भारत का औसत सभी देशों के औसत से ऊपर है। उच्च घाटे के कारण ब्याज दर भी उच्च बनी रहती है जिससे आवास, अचल संपत्ति और वास्तव में सभी औद्योगिक परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नुकसान होता है। एक निश्चित सीमा को पार करने को अवैध बनाने की कोशिश करके भारत ने घाटे के खर्च की प्रवृत्ति को कम करने के बहुत प्रयास किए हैं। २००३ में संसद द्वारा पारित राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून ने राजकोषीय घाटे की सीमा के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के ३ प्रतिशत से अधिक को अवैध बना दिया। फिर भी, हकीकत यह है कि ऐसा एक वर्ष भी नहीं है जब भारत ने इस सीमा को पार नहीं किया है। इसका नतीजा यह है कि राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून (फिस्कल रिस्प न्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ला - एफआरबीएम) दंतहीन हो गया है। महामारी से ठीक पहले कानून की समीक्षा की गई थी और इसका भी कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि कर्ज और घाटे का स्तर अर्थव्यवस्था के लिए निर्धारित स्वस्थ स्तर से कहीं अधिक है। यह सच है कि हंगामाखेज और प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र में मुखर समूहों और निहित स्वार्थों द्वारा अधिक खर्च करने की मांग की जा रही है। इसके शीर्ष पर मुफ्त की पेशकश करने की बढ़ती प्रवृत्ति है। इसके अलावा नई औद्योगिक नीति भी है जो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और आयात से सुरक्षा जैसी योजनाएं प्रदान करती है। अच्छे हों या बुरे हों, इन सभी उपायों के राजकोषीय निहितार्थ हैं जो न केवल ऋ ण और राजकोषीय रुख की स्थिरता को खतरे में डालते हैं बल्कि मुद्रास्फीति के दबाव को भी बढ़ाते हैं। भारत के बारहमासी राजकोषीय प्रभुत्व और बोझ के बड़े और भारी वजन को केवल मौद्रिक नीति को कड़ा करके घटाया नहीं जा सकता है। यहां तक कि यह भी सहनशीलता दिखा रहा है। भारत के लिए मुद्रास्फीति की लड़ाई वास्तव में बहुत कठिन है।

लोकसभा सदस्य गीता मुखर्जी ने की थी महिला आरक्षण विधेयक की शुरुआत

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी ताकतें हमेशा महिला आरक्षण विधेयक के प्रति ढ़ता से प्रतिबद्ध रही हैं और उन्होंने देश में प्रगतिशील महिला आंदोलन के साथ-साथ अपना संघर्ष जारी रखा है। नेशनल फेडरेशन अ फ इंडियन वीमेन (एनएफआईडब्ल्यू) इस संघर्ष को जनहित याचिका के रूप में २०२१ में सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। इस महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने भी कड़ा रुख अपनाया । काफी लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो गया है। जो कोई भी महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए संघर्ष के इतिहास के बारे में जानता है, वह जीत के इस क्षण में क मरेड गीता मुखर्जी को याद करेगा। वह अविस्मरणीय कम्युनिस्ट नेता और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक सतत सेनानी थीं, जिन्होंने महिला विधेयक को पारित करने को एक जीवन मिशन के रूप में लिया।

वह एक सच्ची कम्युनिस्ट थीं जिनका मानना था कि देश की महिलाओं की मुक्तिके बिना भारतीय क्रांति के कार्य पूरे नहीं हो सकते। संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं की तैंतीस प्रतिशत भागीदारी उस दिशा में पहला कदम है। उस पहले कदम को पूरा करने के लिए भी, देश की लोकतांत्रिक ताकतों को दशकों तक लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी। विधेयक का पारित होना महिला संगठनों और अन्य लोकतांत्रिक ताकतों के भविष्य के संघर्षों के लिए एक प्रेरणा होगी।

भाजपा सरकार देश में महिला सशक्तिकरण की चौंपियन बनने की कोशिश कर रही है। उनके सभी प्रचार उपाय इसी के अनुरूप हैं और वे प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी महिलाओं के अधिकारों के योद्धा हैं। चलाये जा रहे ऐसे प्रचार के विपरीत, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के प्रति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हैं। वे वैचारिक और राजनीतिक तौर पर महिला सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं हैं। उनका आरएसएस द्वारा नियंत्रित एक पुरुषवादी संगठन है जिसमें महिलाओं को प्राथमिक सदस्यता से भी वंचित रखा जाता है। उनकी विचारधारा मनुस्मृति द्वारा निर्देशित है, जो न स्त्री स्वतंत्रयंअर्हति (महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए) का उपदेश देती हैं। अचानक, उनकी सरकार नारी शक्ति की पैरोकार बन गई और इस विधेयक के साथ उसे ताज पहनाना चाहती थी। चुनावी मजबूरियां भाजपा के अंदर वैचारिक प्रतिबद्धता पर हावी हो रही थीं। अन्यथा, वे इस विधेयक को शुरू करने के लिए २०१४ से २०२३ तक नौ साल की लंबी अवधि को कैसे उचित ठहरा सकते हैं?

महिला आरक्षण विधेयक की विषयवस्तु को १९९६ में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा आकार दिया गया था, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी महत्वपूर्ण पदों पर थी। तब ओबीसी के लिए आरक्षण को लेकर मतभेद के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका था। इस हेतु गीता मुखर्जी के नेतृत्व में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। हालांकि इसने रिक र्ड समय में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन यह कदम आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि विधेयक लोकसभा के विघटन के साथ समाप्तअवधि वाला हो गया था।

वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई। यूपीए-१, जिसमें वामपंथी दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने मामले को गंभीरता से लिया और महिला आरक्षण विधेयक को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान मिला। ड . मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली इस सरकार के दौरान, विधेयक ६ मई, २००८ को पेश किया गया था। स्थायी समिति की जांच के बाद, राज्यसभा ने ९ मार्च, २०१० को विधेयक पारित कर दिया। उस समय से, राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण इस विषय में कोई गंभीर विकास नहीं हुआ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी ताकतें हमेशा महिला आरक्षण विधेयक के प्रति ढ़ता से प्रतिबद्ध रही हैं और उन्होंने देश में प्रगतिशील महिला आंदोलन के साथ-साथ अपना संघर्ष जारी रखा है। नेशनल फेडरेशन अ फ इंडियन वीमेन (एनएफआईडब्ल्यू) इस संघर्ष को जनहित याचिका के रूप में २०२१ में सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। इस महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने भी कड़ा रुख अपनाया और सरकार को आगाह किया कि अगर विधेयक को लागू करने में और देरी की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

२०२४ के आने वाले लोक सभी चुनावों के साथ-साथ, विभिन्न कारकों ने भाजपा सरकार को कानून के साथ आगे आने के लिए मजबूर किया। हालांकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक मोड़ है, लेकिन भाजपा इसके कार्यान्वयन के प्रति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। आगामी जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के नाम पर, सरकार ने इसके कार्यान्वयन को किसी और समय के लिए विलंबित करने का प्रयास किया है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। देश की लोकतांत्रिक ताकतों ने सरकार से आग्रह किया कि महिला आरक्षण विधेयक को मौजूदा लोकसभा के भंग होने के बाद ही अविलंब लागू किया जाये। पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों में कुल सीटों में से एक तिहाई (३३प्रतिशत) में आधी पर ही महिलाओं के लिए आरक्षण के अनुभव ने हमें दिखाया है कि शासन में महिलाओं को आरक्षण देने से कैसे सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। हमारे राजनीतिक परि श्य में परिवर्तन के लिए यह लैंगिक-समावेशी राजनीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का ईंधन होना चाहिए। वर्तमान अधिनियम का दायरा राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं और परिषदों के साथ-साथ सभी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं तक बढ़ाया जाना चाहिए। कानून बनाने वाली संस्थाओं में ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण एक सार्थक प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

गीता मुखर्जी समिति की रिपोर्ट में भी इस पहलू का जिक्र किया गया है। भाजपा के मंच प्रबंधक, जो अब इस अधिनियम के बारे में शेखी बघार रहे हैं, ने आज तक कभी भी ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। उनकी एकमात्र चिंता नारी शक्ति के नाम पर सत्ता पर कब्जा करना है। महिलाओं के साथ सत्ता साझा करना और सामाजिक न्याय का सम्मान उनके राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे में शामिल नहीं है। उन्हें जनता के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। जीत के इस पहले बिंदु से महिला सशक्तिकरण के संघर्ष को आगे बढ़ाना है। न्याय और मुक्ति के संघर्ष में कम्युनिस्ट महिलाओं और अन्य सभी लोकतांत्रिक ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।

बात बिगड़ेगी तो फिर दूर तलक जाएगी

जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस खेल में जो बाइडेन प्रशासन को भरोसे में ले लिया है, जो उल्टा भारत को सहयोग देने की नसीहत दे रहे हैं। १८ जून को सिख चरमपंथी निज्जर की हत्या हुई। कोई खुफि या इनपुट नहीं। सब कुछ हवा-हवाई। क्या यह संभव नहीं कि स्वयं जस्टिन ट्रूडो ने इस हाई प्रोफाइल खेल को रचा हो? ४ जून २०२३ की बात है। कनाडा के ब्रैंपटन शहर में खालिस्तान समर्थकों ने ५ किलोमीटर लंबी एक परेड निकाली थी। छह जून २०२३ को अ परेशन ब्लू स्टार की ३९वीं बरसी थी। मगर, उससे दो दिन पहलेशोभा यात्रा निकालकर माहौल गर्माने का प्रयास किया गया था। इस शोभा यात्रा में एक चलती हुई गाड़ी पर इंदिरा गांधी की हत्या का दृश्य दिखाया गया था। इसमें खून से सनी साड़ी पहने हुए इंदिरा गांधी का एक पुतला था। दो सिख जवानों के पुतले इंदिरा गांधी के पुतले पर गोलियां बरसाते दिख रहे थे। उस झांकी में एक पोस्टर भी लगाया गया था जिसमें लिखा था, दरबार साहिब पर हमले का बदला।१

८ जून २०२३ को विदेशमंत्री एस. जयशंकर इस आपत्तिजनक झांकी के हवाले से कनाडा के विरूद्ध कड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहां बड़ा मुद्दा कनाडा की जमीन का भारत विरोधी चीजों के लिए इस्तेमाल का है। उन्होंने कहा कि भारत विरोध के लिए कनाडा का इस्तेमाल होना, न हमारे रिश्तों के लिए ठीक है, और न उनके लिए ठीक है। एस. जयशंकर ने एक दायित्व बोध के साथ इस विषय को उठाया था। हमारे मतभेद चाहे जितने रहे हों, मगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री का इस तरह अपमान क्यों कोई भारतीय बर्दाश्त करे। जयशंकर ने जो किया, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन इस समय भारत और कनाडा के बीच जो कुछ चल रहा है, इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति साफ कर देनी चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज डी थ मस ने एक बयान में कहा था कि, भारत उनके देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। वो कौन से आतंरिक मामले हैं? जस्टिन ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को स्पष्ट कर देना चाहिए था। आप अतिवाद को ऊर्जा दो, और उल्टा चोर कोतवाल की तरह व्यवहार करो। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी २०२५ चुनाव तक बचानी है। पूरे देश का ध्यान उन्होंने बांट लिया है। जस्टिन ट्रूडो के साथ मुश्किल यह है कि सरकार को सुचारू रूप से चलाने की बजाय देश का ध्यान भटकाने के लिए कभी चीन से, तो कभी भारत से कूटनीतिक संबंध बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अक्टूबर २०२५ तक सत्ता में बने रहने के लिए जस्टिन ट्रूडो एक कठपुतली प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी को ३३८ सदस्यीय हाउस अ फ क मंस में १७० सभासदों का समर्थन चाहिए। २०१६ के आम चुनाव परिणाम के समय न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) के लीडर जगमीत सिंह किंग मेकर की भूमिका में अवतरित हुए थे। उनके कहने पर ही १८ सिख सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री स्वीकार किया था। २२ मार्च २०२२ को दूसरे आम चुनाव में भी यही सीन था। एक बार फिर सिख सांसदों ने ट्रूडो की कठपुतली सरकार को समर्थन दे दिया। चार साल की यह मियाद २० अक्टूबर २०२५ को पूरी होगी

तीन साल की बच्ची से दस साल के चचेरे मामा ने की दरिंदगी

मासूम के शोर मचाने पर पहुंची मां तो देख उड़े होश

गोरखपुर। गोरखपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है। यहां तीन साल की बच्ची से दस साल के चचेरे मामा ने दुष्कर्म किया। परिवार ने पहले मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन पहले गांव में पंचायत हुई फिर दो दिन बाद शुक्रवार को थाने में केस दर्ज कराया गया। गोरखपुर के जगतबेला क्षेत्र के एक गांव में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी की उम्र महज १० साल है और रिश्ते में बच्ची का चचेरा मामा लगता है। आरोप है कि बच्ची से दुष्कर्म किया गया। पहले तो गांव में दो दिन तक पंचायत चली। फिर शुक्रवार को पीड़िता की मां ने चिलुआताल थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस आरोपी को थाने लाई तो वह रोने लगा। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश सामने आ रही है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित के पिता की मौत हो चुकी है। इस वजह से उसकी मां मायके में रहती है। आरोप है कि चचेरे भाई के १० साल के बेटे ने बुधवार की रात में बच्ची को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर गई तो वह बच्ची के साथ हैवानियत कर रहा था। लेकिन, इसके बाद मामला घरवालों के संज्ञान में आया तो दबाने की कोशिश की गई। गांव में पंचायत के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन शुक्रवार की शाम बच्ची की मां ने डायल ११२ पर दुष्कर्म की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है, उसमें कुछ पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की मां ने आरोपी की उम्र को १२ साल बताया है। पुलिस उम्र का भी सत्यापन कर रही है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी बच्चा है। मेडिकल कराया गया है। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लग रहा है। जांच व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।– मनोज अवस्थी, एसपी नार्थ

मुझे लिंग परिवर्तन करना है...

यूपी पुलिस की पांच महिला सिपाही बनना चाहती हैं पुरुष, डीजी आफिस में लगाई अर्जी

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस की पांच महिला सिपाही अब पुरुष बनना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने डीजी आफिस में प्रार्थना पत्र देकर लिंग परिवर्तन की इजाजत मांगी है। पुलिस अफसर भी ऊहापोह में हैं। गोरखपुर सहित अन्य जिलों के एसपी को पत्र भेजकर काउंसलिंग कराने को कहा गया है। यूपी पुलिस की पांच महिला सिपाहियों ने डीजी आफिस में प्रार्थना पत्र देकर लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी है। इनमें गोरखपुर में तैनात एक महिला सिपाही का भी नाम है। पुलिस महकमे में पहली बार इस तरह का मामला सामने आने के बाद अफसर भी परेशान हैं।

वे अब इसका रास्ता खोजने में लगे हैं। खबर है कि हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक प्रकरण में इसे संवैधानिक अधिकार बता दिया है। हालांकि, डीजी आफिस से इन महिला सिपाहियों के तैनाती वाले जिले के पुलिस कप्तानों को पत्र जारी कर काउंसिलिंग कराए जाने को कहा गया है। पांच में से एक महिला सिपाही सोनम गोरखपुर में तैनात हैं। इसके अलावा गोंडा, सीतापुर में तैनात महिला सिपाहियों ने भी आवेदन किया है। सोनम ने बताया कि डीजी आफिस में प्रार्थना पत्र दी हूं। मुझे बुलाकर पूछा भी गया है। मेरा जेंडर डिस्फोरिया है।

इसका सर्टिफिकेट भी आवेदन में लगाया है। फिलहाल, इस मामले में लखनऊ मुख्यालय से अभी कोई फैसला नही आया है। अगर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो जेंडर चेंज कराने के लिए हाईकोर्ट में भी गुहार लगाऊंगी।

अयोध्या की रहने वाली सोनम बताती हैं कि यूपीपी में २०१६ में उनकी नौकरी लगी। उनकी पहली तैनाकी गोरखपुर में ही है। लिंग परिवर्तन के लिए फरवरी २०२३ से दौड़-भाग शुरू की। इसके बाद से वह गोरखपुर में एसएसपी, एडीजी फिर मुख्यालय तक जा चुकी हैं। सोनम के मुताबिक, पढ़ाई के दौरान ही उनका हार्मोंस चेंज होने लगा था। अब मैं पुरूष बनना चाहती हूं।

दिल्ली के डाक्टर ने भी दी सलाह

सोनम ने बताती हैं कि सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में एक बड़े डाक्टर से कई चरणों में काउंसिलिंग करवाई। इसके बाद डाक्टर ने पाया कि उन्हें जेंडर डिस्फोरिया है। डाक्टर की रिपोर्ट को आधार बनाकर उन्होंने लिंग परिवर्तन करने की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही वह जेंडर चेंज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी ।

बाइक से चलती हैं, स्कर्ट पहनना लगता था अटपटा

सोनम का हाव-भाव और व्यवहार पुरुषों जैसा हो गया है। वह बाल और पहनावे को भी पुरुषों की तरह ही रखती हैं। पल्सर बाइक से चलती हैं। पैंट-शर्ट पहनकर आफिस आती हैं। इसके अलावा वह बुलेट भी चलाती हैं। वह बताती हैं कि जब स्कूल जाती थीं, तब उन्हें स्कर्ट पहनना या लड़कियों की तरह अन्य कोई भी काम करना अटपटा लगता था।

स्कूल में उनकी चाल-ढाल की वजह से कई लोग उन्हें लड़का कहते थे। यह उन्हें अच्छा लगता था। बकौल सोनम, शुरू से ही खुद को कभी लड़की की तरह स्वीकार नहीं किया। स्कूल में खेलकूद होता था तब उनकी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां खो-खो या फिर अन्य लड़कियों वाले गेम खेलने के लिए कहती थीं, तब वह अकेली लड़की थी जो क्रिकेट खेलने की जिद करती थीं।

हाईकोर्ट के फैसले से जगी उम्मीद, बोलीं-वह भी जाएंगी कोर्ट

सोनम ने बताया कि उनकी तरह ही गोंडा की महिला सिपाही ने भी लिंग परिवर्तन कराने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। उसकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लिंग परिवर्तन कराना संवैधानिक अधिकार है। अगर आधुनिक समाज में किसी व्यक्ति को अपनी पहचान बदलने के इस अधिकार से वंचित करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं तो हम सिर्फ लिंग पहचान विकार सिंड्रोम को प्रोत्साहित करेंगे। हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को महिला कांस्टेबल के आवेदन को निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय से अब सोनम को उम्मीद है कि उन्हें भी न्याय मिलेगा। (महिला सिपाही का नाम काल्पनिक है)

गोरखपुर- घर से लापता बच्ची का नाले में मिला शव, पिता ने जताई हत्या की आशंका

गोरखपुर। परिजनों की तहरीर पर पुलिस गुरुवार की रात से ही अपहरण का केस दर्ज कर जांच में जुटी थी। इस बीच, शुक्रवार की सुबह सफाईकर्मी ने नाले में बच्ची के शव को देखा। बच्ची के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। गोरखपुर जिले में तिवारीपुर इलाके के अंधियारी बाग में घर से लापता सात साल की बच्ची की लाश शुक्रवार की सुबह नाले में मिली। परिवारवालों की तहरीर पर पुलिस बृहस्पतिवार की रात से ही अपहरण का केस दर्ज कर जांच में जुटी थी। इस बीच, शुक्रवार की सुबह सफाईकर्मी ने नाले में बच्ची के शव को देखा। बच्ची के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। वहीं, पिता ने बच्ची की हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक, बस्ती जिले के रहने वाले संतोष कुमार मद्धेशिया तिवारीपुर इलाके के अंधियारी बाग में आठ साल से किराए के घर में परिवार संग रहते हैं। संतोष रेती रोड स्थित एक कपड़े की दुकान पर काम करते हैं। परिवार में पति-पत्नी के अलावा दो बेटियां और दो बेटे थे। दूसरे नंबर की बेटी काव्या (७ वर्ष) सूर्य विहार स्थित एक प्राइवेट स्कूल में एलकेजी में पढ़ती थी। संतोष ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात परिवार के सभी लोग घर में थे। इस बीच रात करीब आठ बजे काव्या अचानक घर से खेलते हुए बाहर निकल गई। काव्या ने उस वक्त सिर्फ अंडरवियर और बनियान पहन रखा था। काफी देर बीत जाने के बाद जब वह घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोग तलाश करने लगे। हर तरफ पता करने के बाद भी जब देर रात तक कोई सुराग नहीं लगा तो रात ११ बजे इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें बच्ची अकेले जाते हुए नजर आई थी। पुलिस अभी जांच में जुटी थी कि शुक्रवार की सुबह नगर निगम का सफाईकर्मी नाले की सफाई करने पहुंचा। संतोष के घर से कुछ दूरी पर ही एक मकान के सामने नाले में बच्ची की लाश देखकर सफाईकर्मी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने संतोष को भी बुला लिया। उन्होंने शव की पहचान काव्या के रूप में की।

दो-ढाई फिट गहरे नाले में बच्ची डूबकर नहीं मर सकती। नाले में करीब डेढ़ फिट से अधिक मिट्टी है। बच्ची की हत्या की गई है। – संतोष कुमार मद्धेशिया, पिता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शव पर कहीं चोट के निशान नहीं मिले हैं। बच्ची के फेफड़े में पानी भर गया था। इससे डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।– कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी सिटी।

गोरखपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक

पुलिस चौकी के पास लूटी महिला की चेन

गोरखपुर, संवाददाता। गोरखपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इसका प्रमाण है बेखौफ अपराधियों द्वारा वारदात को दिए जा रहे अंजाम। ताजा मामला शहर के आजादनगर पुलिस चौकी के पास का है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने महिला की चेन लूट ली। शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े लेकिन बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरा फुटेज की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है बड़हलगंज के बेलसड़ा के रहने वाले नरसिंह तिवारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। परिवार के साथ वह फुलवरिया में रहते हैं। उनकी पत्नी सत्यावती देवी शाम में घर से सब्जी खरीदने आजाद चौक जा रही थीं। आजादनगर पुलिस चौकी व जनता स्कूल के बीच पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन लूट ली। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि महिला की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है। राजघाट थाना पुलिस ने चार किलो गांजा के साथ कुशीनगर में बरवापट्टी के भवानीपुर गांव के रहने वाले बृजेश यादव को बाइक समेत गिरफ्तार किया। एसपी सिटी ष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि टीपीनगर चौकी प्रभारी शेर बहादुर यादव शुक्रवार को चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान युवक को पकड़ा तो चार किलो गांजा बरामद हुआ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय

स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देगा डीडीयू लागू होगा इंडियन नालेज सिस्टम

गोरखपुर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के छात्रों को उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इसको लेकर पहल शुरू कर दी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान प्रणाली (इंडियन नालेज सिस्टम) जल्द लागू करने पर विचार किया जाएगा। इसे लेकर कुलपति प्रो. पूनम टंडन और मिनिस्ट्री आफ हायर एजुकेशन की टीम के बीच बुधवार को बैठक की गई। जिसमें खगोल विज्ञान की वैदिक अवधारणाओं से लेकर प्लास्टिक सर्जरी, आयुर्वेद से योग तक भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पाठ्यक्रम शुरू करने पर निर्णय लिया गया।

युवाओं के बीच स्वदेशी भाषाओं और ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय ज्ञान प्रणाली को लागू किया जा रहा है। भारतीय ज्ञान प्रणाली प्राचीन काल से भारत में उच्च स्तर पर विकसित है। कुलपति और उच्च शिक्षा की टीम के बीच हुई बैठक में स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े पाठ्यक्रम पर विचार किया गया।

इसे क्रेडिट पाठ्यक्रम में रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। छात्र को भारतीय ज्ञान प्रणाली में क्रेडिट पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन पाठ्यक्रम के संचालन में एमएचआरडी वित्तीय सहयोग भी प्रदान करेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित इन नए पाठ्यक्रमों में फाउंडेशन और कुछ ऐच्छिक कोर्स हैं।

ऐच्छिक कोर्स में भारतीय भाषा विज्ञान, भारतीय वास्तु शास्त्र, भारतीय तर्क, धातु शास्त्र आदि हैं। इनमें भारतीय ज्योतिषीय उपकरण, मूर्ति विज्ञान, बीज गणित, भारतीय वाद्य यंत्र, जल प्रबंधन भी हैं। फाउंडेशन कोर्स में वेदांग, भारतीय सभ्यता व साहित्य, भारतीय गणित, ज्योतिष, भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान व भारतीय कृषि जैसे विषय शामिल होंगे।

नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान को दिया जा रहा बढ़ावा

नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के छात्रों को उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इसको लेकर पहल शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के छात्रों को उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में खगोल विज्ञान की वैदिक अवधारणाओं से लेकर प्लास्टिक सर्जरी, आयुर्वेद से लेकर योग तक भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

गोविवि कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान प्रणाली (इंडियन नालेज सिस्टम) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर मिनिस्ट्री आफ हायर एजुकेशन टीम के साथ बैठक की गई है। जल्द ही भारतीय ज्ञान प्रणाली को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

यहां चलते-फिरते डेंगू मरीज का प्लेटलेट्स आया 14 हजार, रिपोर्ट देख डाक्टर भी हैरान

गोरखपुर जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीज व उसके घरवालों के होश उस वक्त उड़ गए जब लैब की जांच रिपोर्ट में उसका प्लेटलेट्स काउंट प्रति माइक्रोलीटर रक्त 14000 था। डाक्टर ने तत्काल उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। हालांकि घरवाले उसे एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। जहां इलाज के दौरान अगले दिन जांच की गई तो प्लेटलेट्स काउंट 40000 निकला।

गोरखपुर। जिला अस्पताल की लैब जांच रोगियों का तनाव बढ़ा रही है। डेंगू का एक रोगी प्लेटलेट्स काउंट की जांच रिपोर्ट देखकर घबरा गया। यह घबराहट तब और बढ़ गई, जब डाक्टर ने उसे बीआरडी मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया। रिपोर्ट में उसका प्लेटलेट प्रति माइक्रोलीटर रक्त १४,००० था।

यह था मामला

मेवातीपुर के रहने वाले मिर्जा जहीर बेग ने बताया कि उनके भाई जिला अस्पताल में भर्ती थे। वह चल-फिर रहे थे। जब डाक्टर ने रेफर किया तो हम लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डाक्टर भी यह रिपोर्ट देखकर हैरान थे, क्योंकि इतनी कम प्लेटलेट्स होने पर रोगी चल-फिर नहीं सकता। अगले दिन वहां जांच की गई तो प्लेटलेट्स काउंट ४०,००० निकला, जो उसके दूसरे दिन बढ़कर ८०,००० हो गया। अब वह धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं।

पहले भी आ चुकी है संदिग्ध रिपोर्ट

कुछ दिन पूर्व बिछिया के एक व्यक्ति ने बेटी को बुखार होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। विडाल (टाइफाइड जांच) रिपोर्ट निगेटिव आई तो डाक्टर ने दो दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन बुखार फिर चढ़ गया और पूरे शरीर में दर्द होने लगा। दो दिन बाद निजी अस्पताल में भर्ती होने पर पुनरू जांच की गई तो विडाल रिपोर्ट पाजिटिव आई। टाइफाइड की दवा चली और बेटी ठीक हो गई। बिछिया के ही एक अन्य व्यक्ति ने पेट दर्द होने पर पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। अल्ट्रासाउंड जांच में सबकुछ सामान्य आया, लेकिन पेट दर्द कम नहीं हो रहा था। निजी रेडियोलाजी सेंटर पर जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो किडनी में पथरी निकली।

क्या कहते हैं डाक्टर

जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डा. राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि रेफर करने की बात गलत है, क्योंकि यहां १०,००० प्लेटलेट्स वाले का भी उपचार किया गया और वह ठीक होकर घर गया। डेंगू रोगियों का समुचित उपचार किया जा रहा है।

हंगामा मचा तो भर्ती किए गए अपर नगर आयुक्त

तेज बुखार होने पर अपर नगर आयुक्त द्वितीय निरंकार सिंह को जब कर्मचारी जिला अस्पताल में भर्ती कराने गया तो स्वास्थ्यकर्मी ने मना कर दिया। उसका कहना था कि बेड खाली नहीं है। जब उनके ड्राइवर ने हंगामा शुरू किया और बताया कि अपर नगर आयुक्त हैं, तब आनन-फानन सारे अधिकारी व फिजिशियन मौके पर पहुंच गए। उन्हें भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है।

गोरखपुर में महिलाओं की पूरी भागीदारी युवा वोटर बढ़ाना बड़ी जिम्मेदारी

चुनाव आयोग के मानक पर महिला व युवा वोटरों की संख्या बढ़ाना गोरखपुर जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। यहां लिंगानुपात का मानक 944 है लेकिन जिले में 851 है। वहीं चार की जगह युवा वोटर सिर्फ आधा प्रतिशत हैं। जिले में कुल 35 लाख 87 हजार 46 वोटर हैं। इनमें युवा वोटरों की संख्या महज 20 हजार 141 है।

गोरखपुर। मतदाता सूची को आयोग के मानकों की कसौटी पर खरा उतारना, जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। जनसंख्या के मुताबिक मतदाता सूची में वोटरों का अनुपात तो ठीक है। मगर, लिंगानुपात और पहली बार वोटर बनने वाले १८ से १६ वर्ष के युवा वोटरों की संख्या काफी कम है। आयोग के मुताबिक जिले में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं का अनुपात एक हजार पर ६४४ होना चाहिए। लेकिन, यहां सिर्फ ८५१ है। शहर विधानसभा में सबसे अधिक ८७३ और बांसगांव में सबसे कम ८२६ है।

इसी तरह पहली बार मतदाता बनने वाले १८ से १६ वर्ष के युवाओं की सहभागिता कुल मतदाता संख्या का चार प्रतिशत होना जरूरी है। लेकिन, जिले में सिर्फ ०.५६ प्रतिशत ही है। जिले में कुल ३५ लाख ८७ हजार ४६ वोटर हैं। इनमें १६ लाख ३७ हजार ७२३ पुरुष व १६ लाख ४६ हजार ३६ महिलाएं हैं। युवा वोटरों की संख्या महज २० हजार १४१ है।

मानकों के अनुरूप मतदाता सूची तैयार करने पर जोर

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में गत बुधवार को आयोग के अधिकारियों ने गोरखपुर समेत आस-पास के १६ जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारीधजिलाधिकारी के साथ जीडीए सभागार में बैठक भी की। इसका मुख्य एजेंडा ही मतदाता सूची को मानकों के मुताबिक दुरुस्त करना था। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा ने युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर देते हुए एक जनवरी, २०२४ को १८ वर्ष पूरा करने वाले युवाओं को भी अभियान चलाकर मतदाता बनाने को कहा।

17 अक्टूबर से चलेगा मतदाता अभियान

मतदाता सूची दुरुस्त करने के साथ ही छूटे हुए लोगों को मतदाता बनाने के मकसद से १७ अक्टूबर से विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलेगा। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अभियान के दौरान ३० नवंबर तक मतदाता बनने, नाम काटने, दुरुस्त कराने आदि को लेकर आवेदन किए जा सकते हैं। इसके बाद आवेदनों की जांच, कंप्यूटर में फीडिंग का काम शुरू होगा। पांच जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। लोगों की सहूलियत के लिए अभियान के दौरान प्रत्येक रविवार को मेगा कैंप लगेगा, जिसमें प्रत्येक बूथ पर संबंधित बीएलओ आवेदन पत्रों के साथ मौजूद रहेंगे।

क्या कहते हैं अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने बताया कि मतदाता सूची दुरुस्त कराई जा रही है। १७ अक्टूबर से मतदाता पुनरीक्षण अभियान की भी शुरुआत होगी। इस दौरान वोटर नहीं बने सके लोग आसानी से मतदाता बन सकते हैं। महिला और युवाओं को वोटर बनाने पर जोर रहेगा। इसके लिए गांवों, चौराहों, प्रमुख स्थानों, विश्वविद्यालय, कालेज और शापिंग आदि में विशेष अभियान चलाया जाएगा।

वाराणसी में लालबहादुर शास्त्रीय अस्पताल के फार्मासिस्ट की डेंगू से जिले में पहली मौत

चार नए केस समेत १२१ पर पहुंचा मरीजों का आंकड़ा
मलेरिया विभाग की कार्रवाई में १६ घरों में मिला एंटी लार्वा

वाराणसी। लालबहादुर शास्त्रीय अस्पताल के फार्मासिस्ट की डेंगू से पहली मौत हुई है। चार नए मरीज भी सामने आए हैं। इससे अब कुल मरीजों की संख्या १२१ पर पहुंच गई है। मलेरिया विभाग संपर्क में आए लोगों के घरों व आसपास क्षेत्र में फागिंग और नालियों में एंटी लार्वा रोधी दवा का छिड़काव करा रही है। साथ ही रक्त के नमूने भी लिए जा रहे हैं जिससे डेंगू के बढ़ते मामले को रोका जा सके। अखरी बाइपास निवासी ४२ वर्षीय सुरेंद्र पाल लाल बहादुर शास्त्रीय अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात थे। डेंगू की शिकायत पर क्षेत्र के ही जनता हास्पिटल में इलाज कराया, आराम न होने पर सुंदरपुर स्थित उपकार हास्पिटल में भर्ती हुए। इसके बाद लीवर संबंधित बीमारी होने पर पापुलर अस्पताल में तीन दिन पहले भर्ती हुए, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। डेंगू के चार नए केस साहित्यनाका रामनगर, कोदोपुर, खजुरी व सामने घाट में आए हैं। नगर निगम द्वारा ८७ स्थलों पर एंटी लार्वा का छिड़काव और ७६ घरों में फागिंग का कार्य किया गया।

> यूपी में डेंगू के साथ वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। लालबहादुर शास्त्रीय अस्पताल के फार्मासिस्ट की डेंगू से मौत हो गई। शुक्रवार को डेंगू के चार नए मरीज सामने आए हैं। इससे अब कुल मरीजों की संख्या 121 पर पहुंच गई है। मलेरिया विभाग संपर्क में आए लोगों के घरों में फागिंग और नालियों में एंटी लार्वा रोधी दवा का छिड़काव करा रही है।

२५५६ घरों में लार्वा की जांच की गई है। इस दौरान करौंदी, जानकी नगर, वैष्णो नगर कालोनी, गायत्री नगर, नई सड़क, शिवपुर समेत १६ घरों में एंटी लार्वा पाया गया। ७५६ घरों में ही लार्वा का स्रोत नष्ट करा दिया गया है। मलेरिया अधिकारी शरद चंद्र पांडेय ने बताया कि डेंगू के मच्छर हमेशा दिन में काटते हैं और रात के समय मलेरिया के मच्छर सक्रिय होते हैं। पोस्टर और पैम्फलेट से जागरूक किया जा रहा है। संचारी रोग को देखते हुए लोगों को अपने आसपास साफ-सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है।

लोकसभा चुनाव से पहले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने लगेंगे वाहन

गोरखपुर। लोकसभा चुनाव से पहले ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर संचलन शुरू हो जाएगा। इसके पहले दिसंबर में ही एक लेन आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। मार्च, २०२४ के पहले दूसरा लेन भी शुरू हो जाएगा। इसे लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) के मुताबिक अब तक ७८ प्रतिशत काम पूरा हो गया है। वर्षा और मिट्टी की वजह से पिछले दो महीने तक काम थोड़ा प्रभावित रहा, मगर अब फिर रफ्तार पकड़ने लगा है।

चार घंटे में ही पूरी हो जाएगी लखनऊ की यात्रा

मिट्टी के अनुबंध समझौते की अनुमानित मात्रा में २५ प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ा संकट खड़ा हो गया था। मगर, प्रशासन के प्रयास से यह समस्या भी सुलझ गई है। अब तक १२ लाख डंपर (१.२ करोड़ घन मीटर) मिट्टी का काम पूरा हो चुका है। चार लाख डंपर (४० लाख घन मीटर) मिट्टी का काम अभी बाकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से लखनऊ की दूरी ५रू३० घंटे की बजाए चार घंटे में ही पूरी हो जाएगी। घाघरा नदी पर करीब डेढ़ किमी तक ब्रिज का निर्माण पूरा हो जाने से दिसंबर तक एक लेन खोले जाने की राह आसान हो गई है। पुल पर रेलिंग निर्माण का काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे पर कुल प्रस्तावित ३४२ स्ट्रक्चर (संरचना) में से ३३० बनकर तैयार हो चुके हैं।

यह है लिंक एक्सप्रेसवे का रूट

६१.३५ किलोमीटर लंबा यह लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर के सदर तहसील के जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सालारपुर गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलता है। यह लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संतकबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजर रहा है। इसे वाराणसी के साथ एक अलग लिंक रोड के जरिए जोड़ा जाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे से गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच भी आवाजाही आसान और तेज हो जाएगी। साथ ही गोरखपुर से आगरा और दिल्ली की राह भी आसान हो जाएगी। इसके बन जाने से व्यापारियों को भी बहुत फायदा होगा।

मुआवजा वितरण का काम भी आखिरी चरण में

लिंक एक्सप्रेसवे के लिए तीन तहसीलों सदर, सहजनवां और खजनी के ३५ गांव से जमीन अधिग्रहित की गई है। करीब आधा दर्जन गांव में कुछ ही जमीन का मुआवजा दिया जाना बाकी है। सदर का एक गांव अधिग्रहण से प्रभावित है जहां ६६ प्रतिशत खरीद हो गई है। सहजनवां तहसील के तीन गांवों में से खानीपुर में सिर्फ १७४ एयर और भगवानपुर में ७७ एयर जमीन के मुआवजे का भुगतान बाकी है। इसी तरह खजनी तहसील के भी तीन-चार गांव में ही अधिग्रहण और भुगतान का काम बाकी है।

सपा ने मांगी 65 और कांग्रेस ने 40 लोकसभा सीटें

साझेदारी के लिए राज्यवार बैठक करेगा इंडिया गठबंधन

लखनऊ। इंडिया गठबंधन में अब सबसे अहम मुद्दा सीटों का बंटवारा ही है। सपा जहां पांच राज्यों के चुनावों में गठबंधन के तहत सीटें चाहती है, वहीं लोकसभा सीटों के मद्देनजर भी होमवर्क प्रारंभ हो गया है। यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत सपा ने ६५ और कांग्रेस ने ४५ सीटों पर दावा ठोंका है। जबकि, कुल सीटें ८० ही हैं। सीटों की साझेदारी के लिए इंडिया की समन्वय समिति राज्यवार बैठक करेगी। हालांकि, इस बारे में अंतिम निर्णय तभी हो पाएगा, जब घटक दलों का शीर्ष नेतृत्व साथ बैठेगा। इंडिया गठबंधन में अब सबसे अहम मुद्दा सीटों का बंटवारा ही है। सपा जहां पांच राज्यों के चुनावों में गठबंधन के तहत सीटें चाहती है, वहीं लोकसभा सीटों के मद्देनजर भी होमवर्क प्रारंभ हो गया है। अभी यूपी में सपा के पास तीन और कांग्रेस के पास एक लोकसभा सीट है। इंडिया के सूत्रों के मुताबिक, सपा ने फिलहाल ६०-६५ सीटों पर लड़ने का इरादा जाहिर किया है। वहीं, दावा करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इंडिया गठबंधन का मानना है कि हर राज्य की परिस्तिथितियां अलग-अलग हैं। इसलिए राज्यवार बैठक करके ही सीटों की बंटवारे की गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। ये बैठकें करके सभी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व के सामने विचार के लिए राज्यवार प्रस्ताव रखे जाएंगे।

आठ साल बाद भी अरबों का हिसाब नहीं दिया राज्यों ने, यूपी को उपलब्ध कराना है 10 हजार करोड़ का लेखा

लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों से आवंटित धनराशि के संपूर्ण खर्च का उपभोग प्रमाणपत्र ३० अक्तूबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। यूपी को सर्वाधिक १० हजार करोड़ रुपये का हिसाब देना है। तेरहवें वित्त आयोग को खत्म हुए आठ साल बीतने वाले हैं लेकिन राज्यों ने आयोग से मिली धनराशि का अब तक पूरा हिसाब नहीं दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों से आवंटित धनराशि के संपूर्ण खर्च का उपभोग प्रमाणपत्र ३० अक्तूबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। यूपी को सर्वाधिक १० हजार करोड़ रुपये का हिसाब देना है।

केंद्र सरकार ने १३ वें वित्त आयोग की अवधि २०१०-११ से २०१४-१५ के बीच विभिन्न कार्यों के लिए राज्यों को ८०,०२७ करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यूपी को १०,०१०.०२ करोड़ रुपये जारी किए थे। इसमें एनपीआरडीजी, लोकल ब डी ग्रांट, राज्य आपदा मोचक निधि व राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि व परफार्मेंस ग्रांट के रूप में दी जाने वाली धनराशि शामिल नहीं है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (वित्त आयोग डिविजन) में उप सचिव अनिल गैरोला ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्यों से पूरे या आंशिक उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि दी गई राशि पूरी या आंशिक खर्च नहीं हुई है।

ऐसे में जारी संपूर्ण धनराशि का हिसाब ३० अक्तूबर तक उपलब्ध कराया जाए। गैरोला ने कहा है कि यदि उपभोग प्रमाणपत्र आंशिक दिए गए हैं तो पूरी राशि के लिए मदवार नया उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अपर मुख्य सचिव वित्त को इस संबंध में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

इन कार्यों में खर्च बजट का यूपी को देना है हिसाब। मद और धनराशि (करोड़ रुपये में)...

कैपिसिटी बिल्डिंग 5.00
न्याय तंत्र के विस्तार 246.48
यूनिक आईडी 59.00
डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड 35.00
आईएमआर 17.66
कर्मचारी व पेंशनर डाटाबेस 2.50
सांख्यिकी सिस्टम 28.00
प्राथमिक शिक्षा 5040.00
वन 80.48
अतिरिक्त ऊर्जा 87.76
जल सेक्टर प्रबंधन 341.00
सड़क व पुलों की मरम्मत 2830.00
राज्य केंद्रित आवश्यकता 1216.31

यूपी–संवेदनशील सेक्टरों में विदेशी कंपनियों के हिस्सा लेने पर सशर्त रोक, केंद्र ने यूपी सरकार को दिए निर्देश

लखनऊ। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देखते हुए सरकार कुछ देशों को सरकारी खरीद से बाहर रख सकती है या उनपर कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। संवेदनशील सेक्टरों मे विदेशी कंपनियों के हिस्सा लेने पर सशर्त रोक लगाई गई है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी दिशा-निर्देश दिए हैं। इस पर वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया। पूर्व के नियमों के अनुसार, यदि सरकार का विभाग या एजेंसी किसी परियोजना के लिये बोलियां आमंत्रित करती है और इसे विदेशी बोलीदाताओं (कंपनियों/नागरिक) के लिये खोला जाता है, तो इसमें देशों के आधार पर कंपनियों के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

इसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा संशोधन करते हुए नियम-१४४ (सरकारी खरीद के मूल सिद्धांत) में उप-प्रावधान ११ को जोड़ दिया गया है। इस उप-प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देखते हुए सरकार कुछ देशों को सरकारी खरीद से बाहर रख सकती है या उनपर कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सार्वजनिक खरीद के संदर्भ में केंद्र सरकार के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। नए संशोधन के अनुसार, भारत के साथ थल सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित कंपनियों व नागरिकों को सार्वजनिक खरीद में बोली लगाने का अधिकार तभी दिया जाएगा जब वे 'उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग' द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीत हों। साथ ही उनके लिये विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से क्रमशः राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी।

यह आदेश सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अधीनस्थ निकायों के अलावा सभी स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत चल रहे उन सभी कार्यक्रमों पर लागू होगा, जिन्हें सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र शासित प्रदेशों और इससे जुड़ी एजेंसियों से वित्तीय सहायता मिलती है।

ये हैं संवेदनशील सेक्टर

प्रिंट और डिजिटल मीडिया, परमाणु सेक्टर, रक्षा, अंतरिक्ष, टेलीकम्युनिकेशन, ऊर्जा, बैंकिंग, नागरिक उड्डयन, बांध व नदी घाटी परियोजनाएं, इलेक्ट्रानिक्स, खनन, रेलवे, फार्मा, ंषि, स्वास्थ्य, शहरी ट्रांसपोर्ट, थ्री डी प्रिंटिंग, डाटा टेक्नोलाजी, केमिकल टेक्नोलाजी, सूचना, साफ्टवेयर आदि।

भाजपा की बैठक-2019 में हारी हुई सीटों पर जीत के लिए बनी रणनीति, इस बार मैनपुरी व रायबरेली भी निशाने पर

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पार्टी की लोकसभा प्रवास योजना के तहत मैनपुरी, अंबेडकर नगर, लालगंज, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्रों के संयोजक, प्रभारी और विस्तारकों की बैठक आयोजित हुई। लोकसभा चुनाव २०१६ में हारी हुई १४ लोकसभा सीटों पर २०२४ में जीत के लिए भाजपा प्रत्येक बूथ पर प्रबंधन और सामाजिक समीकरण के हिसाब से चुनावी रणनीति बनाएगी। पार्टी प्रत्येक बूथ पर जीत से ही ८० लोकसभा क्षेत्रों में विजय के मंत्र के साथ काम करेगी।

राजधानी लखनऊ में पार्टी की लोकसभा प्रवास योजना के तहत मैनपुरी, अंबेडकर नगर, लालगंज, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्रों के संयोजक, प्रभारी और विस्तारकों की बैठक आयोजित हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि बूथ स्तर पर सूक्ष्म प्रबंधन और टीमवर्क से ही जीत का लक्ष्य प्राप्त होगा।

कहा कि आगामी दिनों में शुरू हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में नए मतदाता बनवाने का लक्ष्य भी पूरा करना है। कहा कि प्रभारी मंत्री भी लोकसभा क्षेत्र दौरा कर कार्यकर्ताओं से संवाद करें। कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर वहां समस्याओं का समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि हारी हुई सीटों पर मंडल प्रवासी तैनात कर मंडल स्तर पर चुनावी योजना तैयार करें।

विश्वकर्मा, आयुष्मान और महिलाओं पर रहेगा फोकस

सुनील बंसल ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में अधिक से अधिक पात्र लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जोड़ें। आयुष्मान भवः योजना का लाभ भी अधिक से अधिक लोगों को दिलाएं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिये महिला वोट बैंक को साधने की योजना बनाएं। कहा कि, चुनाव में जीत के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद तथा प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य तथा कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है। बैठक में लोकसभा प्रवास योजना के केंद्रीय सदस्य आशीष सूद, प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, प्रदेश महामंत्री अमर पाल मौर्य तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा उपस्थित थे। संचालन कलस्टर इंचार्ज मुकुट बिहारी वर्मा ने किया।

मैनपुरी और रायबरेली भी जीतनी है

१४ लोकसभा सीटों में मैनपुरी और रायबरेली ही ऐसी सीट हैं जहां भाजपा को अब तक एक बार भी जीत नहीं मिली है। बैठक में २०२४ में इन दोनों सीटों पर भी कमल खिलाने पर मंथन हुआ।

80 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करेंगे

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के अनुकूल माहौल बना है। पार्टी २०२४ सभी ८० सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करेगी।

सोशल इंजीनियरिंग मजबूत करें

सुनील बंसल ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक समीकरण के हिसाब से योजना बनाएं। पिछले चुनाव में जिन समाज के वोट नहीं मिले हैं उनका वोट हासिल करने की रणनीति बनाएं।

बूथ स्तर पर तैयार होगी सामाजिक और राजनीतिक योजना

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि पार्टी बूथ सशक्तिकरण अभियान,

बूथ विजय का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। आगामी दिनों में सभी सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर बूथ स्तर तक की कार्ययोजना तैयार होगी।

निष्ठा त्रिपाठी हत्याकांड-मकान में निष्ठा के अलावा थे और चार लोग बीटेक छात्र ने ठिकाने लगाई थी पिस्टल

लखनऊ। बीबीडी की छात्रा निष्ठा त्रिपाठी (२३) हत्याकांड में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात के वक्त घटनास्थल पर निष्ठा के अलावा चार लोग मौजूद थे। वारदात के बाद मुख्य आरोपी आदित्य देव पाठक के दोस्त व बीबीडी के बीटेक छात्र आदित्य शुक्ला ने पिस्टल (आलाकत्ल) जनेवश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर छह के पास ठिकाने लगाई थी। पुलिस ने पिस्टल बरामद कर उसको भी केस में आरोपी बनाया है। केस में आर्म्स एक्ट और साक्ष्य मिटाने की धारा बढ़ाई है। आदित्य शुक्ला की तलाश जारी है। पुलिस ने जांच में आरोपियों के दो दोस्तों को क्लीनचिट दी है। उधर, आदित्य पाठक शुक्रवार को जेल भेजा गया।

हरदोई निवासी संतोष त्रिपाठी यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक में सीनियर मैनेजर हैं। उनकी बेटी निष्ठा बीबीडी से बीक म थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। बुधवार रात को वह चिनहट स्थित दयाल रेजीडेंसी सोसाइटी में किराए पर रहने वाले (मूलरूप से बलिया निवासी) दोस्त आदित्य पाठक के घर पर गई थी। इसी दौरान विवाद के बाद आदित्य ने अवैध पिस्टल से निष्ठा के सीने में गोली मार दी थी। लोहिया अस्पताल में शव छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने आदित्य पाठक और उसके दोस्त मोनू गौतम को पकड़ा था। आदित्य पाठक को गिरफ्तार कर लिया था।

एडीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास ने बताया कि तफ्तीश में सामने आया कि देवरिया निवासी आदित्य शुक्ला बीबीडी से बीटेक कंप्यूटर साइंस का थर्ड ईयर का छात्र है और मुख्य आरोपी का करीबी दोस्त है। जब आदित्य पाठक व मोनू खून से लथपथ निष्ठा को अस्पताल ले गए थे तो दूसरी तरफ आदित्य शुक्ला पिस्टल को ठिकाने लगाने गया था। उसने जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर एक के पास झाड़ियों में पिस्टल फेंकी थी। आदित्य शुक्ला की तलाश में तीन टीमें लगाई गई हैं। देवरिया में भी दबिश दी गई है।

मोनू और अभिषेक नायक को क्लीनचिट, सवाल भी उठे

जिस मकान में आदित्य पाठक किराये पर रहता था, उसके एक कमरे में मोनू भी रहता था। शुक्रवार को पुलिस ने घटना से संबंधित एक प्रेसनोट जारी किया। इसमें बताया गया कि जब निष्ठा को आदित्य पाठक ने गोली मारी तो वहां दूसरे कमरे में मोनू, आदित्य शुक्ला और अभिषेक नायक भी थे। मोनू व आदित्य पाठक निष्ठा को लेकर अस्पताल गए थे। आदित्य शुक्ला पिस्टल छिपाने चला गया था। एडीसीपी के मुताबिक तफ्तीश में स्पष्ट हुआ कि मोनू और अभिषेक नायक की घटना में संलिप्तता नहीं है। हालांकि दोनों की मौजूदगी सवाल खड़े करती है।

भारत पर आरोप लगाकर ट्रूडो ने की बड़ी गलती

अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ बोले– निज्जर और लादेन में अंतर नहीं

न्यूज डेस्क। पेंटागन के पूर्व अधिकारी बोले– यह सबकुछ चुनाव प्रचार के लिए हो रहा है, जिसमें ट्रूडो हारते दिख रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका समेत फाइव आइज देश इस मुद्दे पर कनाडा का साथ नहीं दे रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर आरोप लगाकर कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो फंसते नजर आ रहे हैं।

दरअसल जस्टिन ट्रूडो अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, वहीं भारत ने जिस तरह से कनाडा के आरोपों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है, उससे खुद कनाडा के प्रधानमंत्री भी हैरान होंगे। कनाडा के सहयोगी फाइव आइज (अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया) देशों से भी अब उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने जस्टिन ट्रूडो की तीखी आलोचना की है और आरोप लगाया है कि ट्रूडो बिना सोचे समझे भारत पर आरोप

लगा रहे हैं और इसमें वह फंस गए हैं।

चुनाव के चलते ट्रूडो लगा रहे भारत पर आरोप

पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रुबिन ने भारत कनाडा विवाद पर कहा कि श्मुझे नहीं लगता कि कनाडा के सहयोगी देश जस्टिन ट्रूडो की थ्योरी से सहमत हैं। जब जमाल खाशोगी की इंस्तांबुल में हत्या हुई थी तो उस वक्त तुर्किए ने कई अहम सबूत दिए थे, जिसके चलते सऊदी अरब की दुनियाभर में आलोचना हुई थी।

लेकिन जस्टिन ट्रूडो बिना सोचे समझे आरोप लगा रहे हैं और वह अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर सके हैं। जब ट्रूडो कहते हैं कि उन पर विश्वास कीजिए तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता। यह सबकुछ चुनाव प्रचार के लिए हो रहा है, जिसमें ट्रूडो हारते दिख रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका समेत फाइव आइज देश इस मुद्दे पर कनाडा का साथ नहीं दे रहे हैं।

अमेरिका ने जो लादेन के साथ किया, वो ही भारत ने किया

माइकल रुबिन ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर कोई शरीफ आदमी नहीं था। उसके हाथों पर खून लगा है और वह कई हमलों में शामिल रहा।

हरदीप सिंह निज्जर भी वैसे ही प्लंबर था, जैसे ओसामा बिन लादेन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अपने बयान में कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय उत्पीड़न के खिलाफ हैं लेकिन अगर वह ऐसा कह रहे हैं तो हम पाखंड कर रहे हैं क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय उत्पीड़न नहीं है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद है। अमेरिका ने जो कासिम सुलेमानी के साथ किया या ओसामा बिन लादेन के साथ किया, उसमें और भारत ने जो किया, उसमें अंतर नहीं है।

गलती कर गए हैं ट्रूडो

अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि श्कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने जिस तरह से भारत पर आरोप लगाए हैं, अब वह उनसे पलट भी नहीं सकते क्योंकि वह अगर अपनी बात पर कायम रहते हैं तो उन्हें सबूत पेश करने होंगे और अगर यह साबित भी हो जाता है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत है तो उन्हें इस पर भी जवाब देना होगा कि उन्होंने एक आतंकवादी को क्यों पनाह दी।

अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ बोले– अमेरिका, भारत का साथ देगा

माइकल रुबिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका उस स्थिति में नहीं आना चाहता कि उसे दो दोस्तों में से किसी एक को चुनना पड़े, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम भारत को चुनेंगे क्योंकि निज्जर एक आतंकवादी था और भारत, अमेरिका के लिए अहम भी है। हमारे संबंध महत्वपूर्ण हैं। जस्टिन ट्रूडो लंबे समय तक कनाडा के पीएम नहीं रहेंगे और ऐसे में उनके जाने के बाद हम फिर से संबंध मजबूत कर सकते हैं।

नागपुर में आसमान से बरसी आफत

भारी बारिश से डूबा शहर! लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ तैनात

न्यूज डेस्क। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अंबाझरी झील ओवरफ्लो हो रही है। इसके आसपास का निचला इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित है। नागपुर में शुक्रवार रात आसमान से आफत बरसी। दरअसल शुक्रवार रात से ही रही भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है और हालात ये हैं कि लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती के साथ प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। भारी बारिश से नागपुर की कई सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगह ले जाना पड़ा।

भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात

मौसम विभाग के अनुसार, नागपुर हवाई अड्डे पर सुबह साढ़े पांच बजे तक १०६ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के नागपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और सड़कों पर पानी भर गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अंबाझरी झील ओवरफ्लो हो रही है। इसके आसपास का निचला इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित है। शहर के अन्य हिस्सों में भी कई जगह जलभराव की स्थिति है। बता दें कि डिप्टी सीएम फडणवीस भी नागपुर से ही हैं।

एनडीआरएफ–एसडीआरएफ की टीमें तैनात

डिप्टी सीएम ने नागपुर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को कुछ जगहों पर फंसे लोगों को तुरंत बचाने का निर्देश दिया है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। भारी बारिश से नागपुर के निचले इलाकों में स्थित घरों में पानी भर गया है। अंबाझरी झील इलाके में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने अंबाझरी इलाके से छह लोगों को सुरक्षित बचाया है। अभी भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लोगों को बचाने के लिए अ परेशन चल रहा है। नागपुर के रामदासपेठ इलाके में भी भारी बारिश से बाढ़े के हालात हैं।

वाराणसी पहुंचे सचिन तेंदुलकर

लाल कुर्ता..गले में फूलों की माला

काशी विश्वनाथ धाम में इस अंदाज में आए नजर

वाराणसी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर क्रिकेट की कई हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। इसी क्रम में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर वाराणसी पहुंच गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है। पीएम वाराणसी के गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे।

इस मौके पर क्रिकेट की कई हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। इसी क्रम में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर वाराणसी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सचिन तेंदुलकर को स्प ट किया गया। वाराणसी एयरपोर्ट पर सचिन लाल कुर्ते में नजर आए।

बताया जा रहा है कि रवि शास्त्री भी वाराणसी पहुंच गए हैं।

सचिन तेंदुलकर और रवि शास्त्री एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हुए और बाबा के दरबार में

पूजा-पाठ की। बाबा के धाम में सचिन तेंदुलकर लाल कुर्ता, गले में फूलों की माला और गमछे में नजर आए।

ये रही मेहमानों की लिस्ट

प्रशासन ने जो सूची तैयार की है, उसके मुताबिक गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में पीएम मोदी के मंच पर १८ लोग रहेंगे। इसमें क्रिकेट की हस्तियां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव, करसन घावरी, दिलीप वेंगसरकर, मदनलाल, गुडप्पा विश्वनाथ, यूपी के खेलमंत्री गिरीश चन्द्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या और विधायक त्रिभुवन राम मौजूद रहेंगे।

हत्या–सन्नी नशे में है, रास्ते से हटाने का सही मौका

पत्नी ने प्रेमी को घर बुलाया, फिर पति को दी खौफनाक मौत

सहारनपुर । सहारनपुर जनपद के गागलहेड़ी थानाक्षेत्र में भगवानपुर बाईपास के नजदीक चार माह पहले हुए सन्नी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी और उसके साथी से मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिलाया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी अजय रेलवे में गेटमैन की नौकरी करता है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेसवार्ता में बताया कि गागलहेडी के रविदास मंदिर के समीप रहने वाले सन्नी पुत्र जनेश्वर का शव २६ मई को भगवानपुर बाईपास मार्ग पर गांव चौरादेव के समीप विकास कुमार के खेत से बरामद हुआ था। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। करीब चार माह बाद गुरुवार को मृतक की पहचान हुई। इस मामले में शुरूआत से ही सन्नी की पत्नी मंजू शक के घेरे में थी।

जांच के बाद मंजू से पूछताछ की गई।

पूछताछ के बाद उसके प्रेमी सरसावा के गांव झरोली बहलोलपुर निवासी अजय पुत्र रामपाल और उसके दोस्त इसी गांव के स्वराज पुत्र प्रसाद का नाम भी सामने आया। अजय रेलवे में गेटमैन के पद पर है, जो जगाधरी में तैनात है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम देना स्वीकार किया। हत्याकांड में प्रयुक्त आरोपियों की बाइक भी कब्जे में ली है।

शादी के बाद भी था प्रेमी से संपर्क

पूछताछ के दौरान मंजू ने बताया कि उसकी शादी करीब १० साल पूर्व सन्नी से हुई थी। मगर हत्यारोपी अजय के साथ शादी से पहले ही उसके प्रेम संबंध थे।

मंजू के मामा हत्यारोपी अजय के गांव के ही रहने वाले हैं, जहां शादी से पहले मंजू का आना-जाना था। मंजू और अजय दोनों शादी करना चाहते थे। मगर उनके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे। इसी के चलते परिजनों ने मंजू की शादी सन्नी से कर दी थी। शादी होने के बाद सन्नी को मंजू के प्रेम संबंधों के बारे में पता चल गया था। इस वजह से अजय का मंजू के घर आना-जाना बंद हो गया था। मंजू और अजय ने मिलकर सन्नी को मारने की योजना बनाई।

नशे की हालत में घर से ले गए थे आरोपी

पुलिस के अनुसार, २८ मई को मंजू का फोन अजय के पास आया। उसने बताया कि सन्नी इस समय नशे की हालत में है और उसे रास्ते से हटाने का यही मौका है। इसके बाद अजय अपने दोस्त स्वराज को लेकर बाइक से मंजू के घर पहुंचा। जहां से मंजू ने नशे की हालत में सन्नी को उनकी बाइक पर बैठा दिया। दोनों बाइक से सन्नी को साथ लेकर भगवानपुर बाईपास मार्ग पर सुनसान जगह में पहुंचे और सन्नी की बेल्ट से ही गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी।

मां को कैंसर है...

ये बताते हुए भावुक हुई साउथ अभिनेत्री कहा– डाक्टरों पर भरोसा करना जरूरी

एंटरटेनमेंट डेस्क। प्रिया भवानी शंकर ने कहा कि वह कैंसर की वजह से अपनी मां को खोना नहीं चाहती हैं। इसके साथ ही प्रिया ने मरीजों से बातचीत की और उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। साउथ अभिनेत्री प्रिया भवानी शंकर सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने एक न्यूज एंकर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद टीवी जगत में अपना कदम रखा। कुछ साल टीवी सीरियल्स में काम कर उन्होंने बड़े पर की ओर अपना रुख मोड़ लिया। हाल ही में श्विश्व गुलाब दिवसश के मौके पर वह एक निजी अस्पताल के कैंसर केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचीं। यह कार्यक्रम कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ने वालों को प्रेरित करने के लिए था।

मां के बारे में बताते हुए रो गई प्रिया

थिरुचित्रम्बलम अभिनेत्री ने इस दौरान बताया कि उनकी मां को पिछले साल ही कैंसर का पता चला था। इसे बताते हुए प्रिया रो गईं। प्रिया भवानी ने कहा, पिछले साल, मेरी मां को कैंसर का पता चला था। डाक्टरों ने मुझे भी टेस्ट कराने के लिए कहा था, जब वह बीमार थीं, तो मैं अक्सर उससे कहती थी कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगीं। क्योंकि इसका पता शुरुआत में ही चल गया था, जिस कारण हम उसका इलाज करने में सक्षम हैं। आज यह देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग यहां आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए।

ऐश्वर्या संग रोमांटिक सीन करने में घबरा गए थे रजनीकांत

मरीजों से बातचीत कर दी सांत्वना

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि वह कैंसर की वजह से अपनी मां को खोना नहीं चाहती हैं। उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कहा कि सबसे जरूरी है कि डाक्टरों पर भरोसा करना होगा। इसके साथ ही प्रिया ने मरीजों से बातचीत की और उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी।

परिणीति की शादी का हिस्सा नहीं बनेंगी प्रियंका! दिया हिंट

कमल हासन की इस फिल्म में आएंगी नजर

वहीं उनके वर्कफ्रंट की बात की जाए तो वह आखिरी बार फिल्म बोम्मई में नजर आई थीं। राधा मोहन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एसजे सूर्या थे। युवान शंकर राजा ने फिल्म को संगीत दिया था। इसके अलावा जल्द ही वह फिल्म डेमोंटे क लोनी २ में नजर आएंगी। इसमें अरुलनिथि और मीनाक्षी गोविंदराजन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। आर. अजय ज्ञानमुथु ने इस फिल्म को निर्देशित किया है। इसके साथ ही वह तेलुगु फिल्म जेबरा में दिखाई देंगी। हाल ही में प्रिया भवानी ने खुलासा किया कि वह कमल हासन की फिल्म इंडियन २ में नजर आएंगी।

नायक नहीं पर्दे पर खलनायक बन प्रेम चोपड़ा ने बनाई पहचान

इस एक गलती ने बदल दी अभिनेता की जिंदगी

एंटरटेनमेंट डेस्क। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा आज यानी २३ सितंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। प्रेम का नाम ब लीवुड के उन सितारों में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी पहचान एक नायक के तौर पर नहीं, बल्कि खलनायक के तौर पर बनाई है। अपने दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेने वाले प्रेम का जन्म १९३५ में लाहौर (जो अब पाकिस्तान) में हुआ था। इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए अभिनेता को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ा।

प्रेम चोपड़ा ने बालीवुड में अपने करियर की शुरुआत सन् १९६४ में आई फिल्म वो कौन थी से शुरू किया। इस फिल्म में अभिनेता विलन के किरदार में नजर आए थे। यह वो दौर था, जब इंडस्ट्री में काम पाने के लिए अभिनेता भटक रहे थे। इस बीच ट्रेन में उनकी मुलाकात एक शख्स ने सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार महबूब खान से करवाई। महबूब खान ने प्रेम चोपड़ा को देखकर उनसे वादा किया वह फिल्मों में उन्हें मुख्य अभिनेता को रोल देंगे।

मगर इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रेम इसके लिए मान गए और इस बीच उन्हें वो कौन थी में काम करने का आफर मिला। एक्टर ने हामी भर दी और फिल्म बाक्स आफिस पर हिट साबित हुई। सिनेप्रेमियो को उनका यह खलनायक अंदाज काफी पसंद आया और एक्टर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अपने करियर के दौरान उन्होंने लगभग ४०० से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।

इसके बाद प्रेम जब अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग करत रहे थे तब महबूब खान प्रेम चोपड़ा से मिले और उन्होंने उन्हें डांटा और कहा कि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। महबूब खान ने फिर प्रेम चोपड़ा से कहा कि तुमने फिल्म वो कौन थी? में इतना बेहतरीन विलेन का किरदार किया है कि वह दर्शकों के दिलों पर छप गए है। इसलिए अब तुम यही करो। इससे बेहतर और कुछ नहीं है।

प्रेम चोपड़ा ने हिंदी ही नहीं, बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। शुरुआत में उन्होंने फिल्मशहीद में सुखदेव का रोल निभाया था, जिसे लोगों ने खूब सराहा था। फिर उपकार में विलेन बने और कई फिल्मों में खलनायक बनकर ही उन्होंने सिनेमा जगत में मुकाम हासिल कर लिया। प्रेम चोपड़ा ने शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, दो रास्ते, कटी पतंग, दो अनजाने, जादू टोना, काला सोना, दोस्ताना, क्रांति, फूल बने अंगारे जैसी फिल्मों में काम किया है, जिनके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे।

मुम्बई। तनुजा 23 सितंबर 1943 को पैदा हुई थीं। तनुजा ने कम उम्र में ही अपने अभिनय से सभी को हैरान कर दिया। शरत अकेली है, बुझ गए दिए जैसे गाने में आपने तनुजा को सिडक्टिव अवतार में भी देखा होगा और देव आनंद के गाने ये दिल न होता बेचारा में तनुजा को गुस्सा दिखाते भी देखा होगा। दोनों ही गाने आज तक मशहूर है। कहा जाता है तनुजा को परिवार की माली हालत की वजह से 16 साल की उम्र में ही डेब्यू करना पड़ा था। उस समय वो स्विट्जरलैंड के सेंट जश्वर्ज स्कूल में पढ़ती थीं। तब तनुजा के घर की माली हालत ठीक नहीं रही और उन्हें घर वापस आना पड़ा। उनकी मां ने उन्हें कहा कि या तो वो इसका दुख मना सकती हैं या फिर हिंदी सिनेमा में काम कर सकती हैं। यह सुनकर तनुजा ने हिंदी फिल्मों को चुना। उसके बाद 16 साल की उम्र में 1960 में उनकी पहली फिल्म छबीली रिलीज हुई और इसके बाद 1962 में मेम दीदी। तनुजा की डेब्यू फिल्म छबीली के दौरान का उनका एक किस्सा काफी मशहूर है। दरअसल, फिल्म के एक सीन में तनुजा को रोना था लेकिन वो बार-बार हंस रही थीं। तनुजा ने केदार शर्मा से कहा कि आज मेरा रोने का मूड नहीं है। इसी बात से नाराज होकर केदार शर्मा ने तनुजा को जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। तनुजा ने पूरी बात मां को बताई तो उल्टा तनुजा को एक और थप्पड़ जड़ दिया। क्योंकि वो तनुजा के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थीं। फिर शोभना, तनुजा को वापस सेट पर लेकर गईं और केदार शर्मा से कहा कि अब ये रो रही है, शूटिंग शुरू कर दीजिए। इसके बाद तनुजा ने परफेक्ट शाट दिया। तनुजा ने कई बंगाली फिल्में भी की हैं। वहीं तनुजा के हिसाब से बंगाली फिल्में उन्हें ज्यादा संतुष्टि देती थीं। शोमू मुखर्जी से तनुजा की मुलाकात फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर हुई थी। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा और दोनों ने साल 1973 में शादी कर ली। उसके बाद दो बेटियों काजोल और तनीषा का जन्म हुआ।

सबसे आगे हिंदुस्तानी

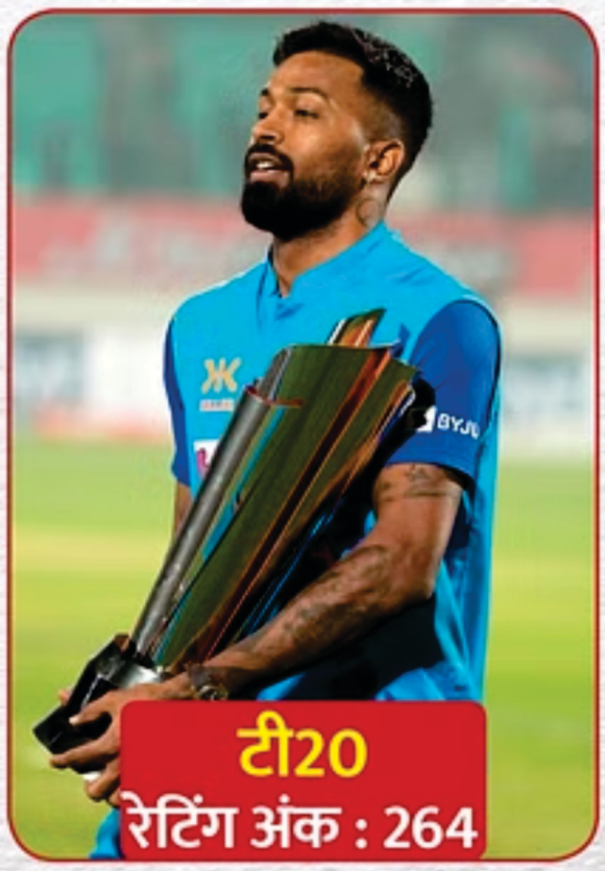

भारत ने रचा इतिहास

आईसीसी के तीनों फार्मेट में नंबर-1 बना वनडे में पाकिस्तान को पीछे छोड़ा

स्पोर्ट्स डेस्क। आस्ट्रेलिया ने ५० ओवर में २७६ रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने ४८.४ ओवर में २८१ रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज शुक्रवार (२२ सितंबर) को शुरू हुई। टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने ट स जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अ स्ट्रेलिया ने ५० ओवर में २७६ रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने ४८.४ ओवर में २८१ रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया। वह टी२० और टेस्ट में पहले ही शीर्ष पर था। इस तरह भारत एक ही समय में तीनों फार्मेट में नंबर-१ बन गया है।

केएल राहुल की कप्तानी में मिली जीत के साथ ही टीम इंडिया इतिहास रच दिया। वह एक ही समय में तीनों फ मैट में पहले स्थान पर पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा किया था। वह अगस्त २०१२ में एक साथ टेस्ट-वनडे और टी२० में पहले पायदान था।

पाकिस्तान से आगे निकला भारत

आस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद वनडे में भारत के ११६ रेटिंग अंक हो गए। उसने पहला स्थान हासिल करते हुए पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी टीम को ११५ रेटिंग अंक हैं। आस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर कायम है। उसके १११ रेटिंग अंक हैं।

ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में नंबर-1 टीम के तौर पर नहीं जाएगा

हार के परिणामस्वरूप, आस्ट्रेलियाई टीम विश्व कप में नंबर-१ टीम के तौर पर नहीं जाएगी। भारत के खिलाफ बाकी बचे दो मैच जीतने के बावजूद पर वह शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। हालाँकि, अगर आस्ट्रेलिया बाकी दोनों मैच जीत जाता है तो भारत पहले स्थान पर नीचे आ सकता है और पाकिस्तान शीर्ष पर पहुंच सकता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच में क्या हुआ?

मोहाली में खेले गए वनडे में टास हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आस्ट्रेलिया ने ५० ओवर में सभी १० विकेट गंवाकर २७६ रन बनाए। डेविड व र्नर ने ५२, जोश इंग्लिश ने ४५ और स्टीव स्मिथ ने ४१ रन की पारी खेली। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने पांच विकेट लिए। जवाब में ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए १४२ रन जोड़े। ऋतुराज ने ७१ रन और शुभमन गिल ने ७४ रन की पारी खेली। वहीं, सूर्यकुमार यादव ५० रन बनाकर आउट हुए। कप्तान केएल राहुल ने ५८ रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने ४६वें ओवर में शान एबाट की गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई।

आईसीसी ने प्राइज मनी का किया एलान

विजेता को मिलेंगे 33 करोड़ रुपयेय देखें पूरी लिस्ट

स्पोर्ट्स डेस्क। विश्व कप के १३वें संस्करण में १० टीमें ट्र फी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। मेजबान भारत के अलावा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और नीदरलैंड की टीमें खेलेंगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आगामी पुरुष वनडे विश्व कप के लिए प्राइज मनी का एलान कर दिया है। आईसीसी ने टूर्नामेंट में प्राइज मनी का बजट ८२.६३ करोड़ रुपये (१० मिलियन अमेरिकी ड लर) रखा है। विश्व कप की मेजबानी भारत के पास है। पांच अक्तूबर को गत विजेता इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल १६ नवंबर को होगा। उद्घाटन और फाइनल दोनों मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होंगे।

आईसीसी ने शुक्रवार (२२ सितंबर) को बताया कि विजेता टीम को ३३.१७ करोड़ रुपये (चार मिलियन अमेरिकी ड लर) मिलेंगे। फाइनल में हारने वाली टीम को १६.५६ करोड़ रुपये (दो मिलियन अमेरिकी ड लर) से संतोष करना पड़ेगा।

ग्रुप चरण में सभी १० टीमें राउंड-राबिन प्रारूप में एक-दूसरे से खेलेंगी। अंक तालिका में शीर्ष चार में रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। २०१६ में भी इसी फार्मेट में टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था।

सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने वाली टीमों को भी मिलेंगे पैसे

ग्रुप राउंड में मैच जीतने पर भी पुरस्कार राशि दी जाती है। टीमों को प्रत्येक जीत के लिए ३३.१७ लाख रुपये (४०,००० अमेरिकी डालर) मिलेंगे। ग्रुप स्टेज के अंत में जो टीमें नाकआउट में पहुंचने में विफल रहेंगी, उनमें से प्रत्येक को ८२.६२ लाख रुपये (१००,००० अमेरिकी डालर) मिलेंगे।

किस राउंड में कितने रुपये मिलेंगे

राउंड प्राइज मनी

विजेता ३३.१७ करोड़ रुपये (चार मिलियन अमेरिकी डालर)

उप-विजेता १६.५६ करोड़ रुपये (दो मिलियन अमेरिकी डालर)

सेमीफाइनल में हारने पर ६.६३ करोड़ रुपये (८००,००० अमेरिकी डालर)

ग्रुप राउंड में बाहर होने पर ८२.६२ लाख रुपये (१००,००० अमेरिकी डालर)

ग्रुप राउंड में हर मैच जीतने पर ३३.१७ लाख रुपये (४०,००० अमेरिकी डालर)

विश्व कप में होंगे 48 मुकाबले

विश्व कप के १३वें संस्करण में १० टीमें ट्राफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। मेजबान भारत के अलावा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और नीदरलैंड की टीमें खेलेंगी। १० टीमों के बीच कुल ४८ मुकाबले खेले जाएंगे। विश्व कप की शुरुआत से पहले प्रत्येक टीम ४६ दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट के लिए तैयार होने के लिए दो अभ्यास मैच खेलेगी।

दी नेक्स्ट पोस्ट
स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिनः- 273003
Tital code: UPHIN51019

बृजेन्द्र कुमार
मो0. नं0. 7307180148,9170772370
Email- thenextpost01@gmail.com

नोटः- समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद-विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे।